राजस्थान राज्य

बनाम

राम सारन

(बी. पी. सिन्हा सी. जे. जे. सी. शाह और एन. राजगोपाल अय्यंगार जे. जे.)

अजमेर में लोक सेवक-राज्य पुनर्गठन में पुलिस का कार्यवाहक उप-निरीक्षक-राजस्थान-पुलिस प्रत्यावर्तन-कानूनी अधिनियम, 1861 (1861 का 5), धारा 115, 116, 117 में उसी पद पर नियुक्त 2, 12- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37)

प्रतिवादी अजमेर में पुलिस का एक कार्यवाहक उप-निरीक्षक था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राजस्थान राज्य में अजमेर के विलय के बाद, प्रतिवादी को राजस्थान में पुलिस का कार्यवाहक उप-निरीक्षक नियुक्त किया गया था। 6 अप्रैल, 1957 को उन्हें हेड कांस्टेबल के अपने मूल पद पर वापस भेज दिया गया। उन्होंने अपनी वापसी को इस आधार पर चुनौती दी कि अजमेर में पुलिस बल के स्थायी आदेशों के तहत, जो उनकी सेवा की शर्तों का हिस्सा थे, उन्हें कनिष्ठता के सख्त क्रम को छोड़कर वापस नहीं किए जाने का गारंटीकृत अधिकार था, कि वापसी उनकी सेवा की शर्तों में एक परिवर्तन था जिसे राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लागू करने में सक्षम नहीं थी अधिनियम 15(7) और यह कि धारा 117 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक निर्देश था। उस अधिनियम का, जिसने सेवा की शर्त को वापस लिए बिना किसी कार्यवाहक पद को बनाए रखने का अधिकार दिया।

अभिनिर्धारित किया कि स्थायी आदेश केवल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा धारा 12 पुलिस अधिनियम के तहत जारी किए गए प्रशासनिक निर्देश थे। और सेवा की शर्तें नहीं थीं जो केवल राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा सकती थीं। इस प्रकार, भले ही प्रत्यावर्तन के आदेश ने स्थायी आदेश का उल्लंघन किया हो, सेवा की शर्तों का कोई

उल्लंघन नहीं था। यह सेवा की शर्त नहीं है कि किसी कार्यवाहक पद के धारक को उसके मूल पद पर वापस नहीं किया जाएगा और धारा द्वारा विचार किए गए प्रत्यावर्तन के आदेश द्वारा सेवा की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। पुनर्गठन अधिनियम, 1956 115(7) न ही धारा 117 के तहत केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्देश दिया गया था। इस संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों को कम करने वाला अधिनियम। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति के संबंध में "ऐसे पद या पद पर उसके बने रहने को प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश" पारित करने की राज्य सरकार की शक्तियों को विशेष रूप से धाराद्वारा संरक्षित किया गया है। अधिनियम की धारा 6(2) किसी अधिकारी को कार्यवाहक पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह यह दावा नहीं कर सकता कि उचित कारणों के अलावा उसे वापस नहीं किया जा सकता है। परशोतम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ, (1958) एस. सी. आर. 828, में संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः दीवानी याचिका सं 453/1962

राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल रिट सं. 264/1959 में 18 नवंबर, 1960 के निर्णय और आदेश से अपील।

अपीलकर्ता की ओर से एस. के. कपूर, के. के. जैन और पी. डी. मेनन।

बी. डी. शर्मा, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय अय्यानगर जे. द्वारा 10 अप्रैल 1963 को पारित किया गया था।

राजस्थान राज्य इस अपील में अपीलकर्ता है जो संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (सी) के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए योग्यता प्रमाण पत्र के अनुसार दायर की गई है और यह प्रत्यर्थी द्वारा दायर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता को चुनौती देता है।

प्रतिवादी राम सरन को 1947 में अजमेर जिला पुलिस बल में सिपाही नियुक्त किया गया था। इसके दो साल बाद उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया और उस पद पर उनकी पुष्टि की गई। 29 जून, 1956 को उन्हें उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उस स्तर पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956 का XXXVII), जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया था, अधिनियमित किया गया था-जो 1 नवंबर, 1956 से लागू हो गया था, जिसे अधिनियम में निर्धारित तिथि के रूप में संदर्भित किया गया था, और इसके प्रावधानों के आधार पर 984 पूर्व राज्य अजमेर का राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया था और इसकी शर्तों के तहत फिर से प्रतिवादी को राजस्थान राज्य की पुलिस सेवा में शामिल कर लिया गया था। इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्यर्थी को राजस्थान राज्य पुलिस बल में कार्यवाहक उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त करने का एक औपचारिक आदेश भी उसी दिन पारित किया गया था।

इसके बाद, 6 अप्रैल, 1957 को पुलिस उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज ने प्रतिवादी को जिला पुलिस बल में हेड कांस्टेबल के अपने मूल पद पर वापस ले जाने का आदेश दिया। प्रत्यर्थी इस आदेश से असंतुष्ट था और उसकी शिकायत थी कि यह नियुक्ति के सामान्य क्रम में पारित नहीं किया गया था क्योंकि उस तारीख को राज्य पुलिस बल में कार्यवाहक उप-निरीक्षक थे जो उससे कनिष्ठ थे, लेकिन जो अपने कार्यवाहक पदों पर बने रहे और यह कि उनके मूल पद पर इस तरह का परिवर्तन प्रभावी रूप से अतिक्रमण का आदेश था। उन्होंने मामले को ठीक करने के लिए अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया। जब वे अपने प्रयासों में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने 22 जुलाई, 1959 को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 6 अप्रैल, 1957 के प्रत्यावर्तन के आदेश को रद्द करने और उन्हें कार्यवाहक के पद पर बहाल करने के निर्देश के लिए एक याचिका दायर की। अपनी वरिष्ठता के अनुसार उप-निरीक्षक राज्य

के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक को याचिका के पक्षकारों के रूप में शामिल किया गया था और उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने इसे मुख्य रूप से इस आधार पर अनुमति दी कि प्रत्यावर्तन का यह आदेश धारा 115 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। यह इस आदेश की शुद्धता है जिसे हमारे समक्ष इस अपील में चुनौती दी गई है।

उठाए गए तर्कों की सराहना आदेशने के लिए उन वैधानिक प्रावधानों को संक्षेप में विज्ञापित आदेशना आवश्यक है जिन पर मुख्य रूप से उच्च न्यायालय का निर्णय निहित है। इसमें वे सामग्री; 985 संदर्भ धारा 115 धारा 117 हैं। भाग 10 में आने वाले अधिनियम में 'सेवाओं के बारे में प्रावधानः

> "115. (1). प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से तुरंत पहले उप-राज्यपाल या मुख्य आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अजमेर, भोपाल, कुर्ग, कच्छ और विंध्य प्रदेश के किसी भी मौजूदा राज्य में संघ के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है, या मैसूर, पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ और सौराष्ट्र के मौजूदा राज्यों में से किसी के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है, उस दिन से, यह माना जाएगा कि उसे उस मौजूदा राज्य के उत्तराधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में सेवा करने के लिए आवंटित किया गया है।
>
> (2)...............
>
> (3)...............
>
> (4)...............

(5) केंद्र सरकार आदेश द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियों की स्थापना कर सकती है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के संबंध में उसकी सहायता करना है -

(क) नए राज्यों और आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों के बीच सेवाओं का विभाजन और एकीकरण; और

(ख) इस खंड के प्रावधानों से प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन पर उचित विचार करना।

(6) इस खंड के चालू प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिन पर खंड 114 के प्रावधान लागू होते हैं -

(7) इस खंड की कोई बात नियत दिन के बाद संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के निर्धारण के संबंध में संविधान के भाग XIV के अध्याय I के प्रावधानों के प्रवर्तन को प्रभावित करती नहीं समझी जाएगीः

बशर्ते कि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में नियत दिन से तुरंत पहले लागू होने वाली सेवा की शर्तों में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा उसके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा।

(1). प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से तुरंत पहले किसी क्षेत्र में किसी विद्यमान राज्य के मामलों के संबंध में किसी पद या पद के कर्तव्यों को धारण या निर्वहन कर रहा है, उस दिन से ऐसा समझा जाएगा कि वह ऐसे राज्य की सरकार या अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा या केंद्र

सरकार या ऐसे भाग ग राज्य में अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, उस पद या पद पर विधिवत नियुक्त किया गया है।

2). इस खंड की कोई बात किसी सक्षम प्राधिकारी को, नियत दिन के बाद, ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे पद या पद पर उसके बने रहने को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित करने से रोकने वाली नहीं मानी जाएगी। केंद्र सरकार नियत दिन से पहले या बाद में किसी भी समय किसी भी राज्य सरकार को ऐसे 987 निर्देश दे सकती है जो उसे इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत हों और राज्य सरकार ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।"

इन प्रावधानों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक मामले को दरकिनार करना सुविधाजनक होगा और वह यह है कि यह सुझाव नहीं दिया गया था कि प्रत्यावर्तन का आदेश सजा के रूप में एक था जो संविधान के अनुच्छेद 311 को आकर्षित करने के लिए रैंक में कमी का गठन करता है।

हमारे समक्ष प्रत्यर्थी की शिकायतें तीन गुना थी: (1) कि पदोन्नति के उद्देश्य से और प्रत्यावर्तन निर्धारित करने के लिए पुलिस बल में वरिष्ठता की गणना पूरे राजस्थान राज्य के लिए तैयार की गई वरिष्ठता की सूची के आधार पर नहीं की गई थी, बल्कि यह कि यह क्षेत्रीय आधार पर किया गया था, यानी कि अजमेर के लिए एक अलग वरिष्ठता सूची थी और राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए एक अलग वरिष्ठता सूची थी और इसके परिणामस्वरूप उनके जैसे अन्य कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को केवल इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि वे एक विशेष क्षेत्र में सेवारत थे। याचिका में ऐसी क्षेत्रीय सूचियों के रखरखाव का एक अस्पष्ट संदर्भ था जो अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत समानता का उल्लंघन करता है, (2) प्रतिवादी द्वारा आगे यह तर्क दिया गया था कि उप-निरीक्षक

के कार्यवाहक पद से हेड कांस्टेबल के मूल पद पर वापस जाना "उसकी सेवा की शर्तों में एक परिवर्तन" था जिसे राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लागू करने में सक्षम नहीं थी। अधिनियम की धारा 5 (7) और यह कि, किसी भी स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा धाराके तहत एक निर्देश दिया गया था। 117 उस अधिनियम का, जो ऐसी शर्त के रूप में प्रत्यावर्तन के बिना किसी कार्यवाहक पद को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है, (3) भले ही धारा 115 988 को "सेवा की शर्त" के रूप में एक मूल पद पर वापस किए बिना एक कार्यवाहक पद को बनाए रखने के अधिकार का गठन करने के लिए अपने आप में अपर्याप्त थे, फिर भी पुलिस बल के स्थायी आदेशों के प्रावधानों के तहत कनिष्ठता के सख्त क्रम को छोड़कर वापस नहीं किए जाने का एक गारंटीकृत अधिकार था जो उनकी सेवा की शर्तों का हिस्सा थे और इन स्थायी आदेशों के कारण प्रत्यावर्तन धाराओं का उल्लंघन था।

हम मानते हैं कि इनके साथ विपरीत क्रम में व्यवहार करना सुविधाजनक होगा, और पहले उस स्थायी आदेश की व्याख्या और प्रभाव पर विचार करना होगा, जिस पर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के साथ-साथ हमारे समक्ष प्रतिवादी के विद्वान वकील दोनों द्वारा भरोसा किया गया है। उनके संबंध में दो अलग-अलग प्रश्न हैं (1) उनकी उचित व्याख्या, (2) क्या वे कानूनी रूप से सेवा की शर्त का गठन करेंगे और इन पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। जिस स्थायी आदेश पर भरोसा किया गया है, वह पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर द्वारा जारी 46 नंबर का है और 20 अक्टूबर, 1949 का है। इसके प्रासंगिक भाग पर पैराग्राफ 4 (बी) है जो पढ़ता है:

> "एक अधिकारी जिसने अनुमोदित सूची में अपने स्थान के आधार पर कार्यवाहक प्रस्ताव प्राप्त किया है, उसे आम तौर पर पदोन्नति के लिए पहले विचार किया जाना चाहिए बशर्ते कि वह एक उपयुक्त मानक बनाए रखे। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे वापस

किया जा सकता है या उसकी पुष्टि को स्थगित किया जा सकता है। हालाँकि, उन्हें पुष्टि के अपने दावे से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हालांकि झूठ ने अपने मानक को बनाए रखा है, लेकिन बाद में पदोन्नत किसी अन्य व्यक्ति को और भी बेहतर माना जाता है।"

इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यह उस आदेश से संबंधित नहीं है जिसमें कार्यवाहक पदों के धारकों को वापस किया जा सकता है, बल्कि उस आदेश से संबंधित है जिसमें उन्हें पुष्टि के लिए विचार किया जा सकता है, ताकि अपनी भाषा पर सख्ती से खंड 989 आक्षेपित प्रत्यावर्तन को अपनी शर्तों के भंग के रूप में गठित न करे। लेकिन यह मानते हुए कि जिसे नियम की भावना या इसके पीछे के कारण कहा जा सकता है, उस पर विचार किया जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि यह उस क्रम को भी निर्धारित आदेशता है जिसमें प्रत्यावर्तन होना चाहिए, फिर भी हमें इस बात पर विचार आदेशना होगा कि क्या इसकी सेवा शर्त के रूप में कोई कानूनी प्रभावकारिता है। यह एक अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेशों पर निर्भर करेगा जो उस प्राधिकरण को "सेवा की शर्तों" को निर्धारित करने का अधिकार देता है। क्योंकि निस्संदेह यदि ऐसा नहीं होता तो यह केवल अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी एक प्रशासनिक निर्देश होता, लेकिन अधिनियम या सक्षम अधिकारियों द्वारा वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकता था या कोई अधिनियमी अधिकार प्रदान नहीं कर सकता था जो गैर-पालन की स्थिति में अदालत में शिकायत का विषय हो सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को यह पता लगाने में कठिनाई हो रही थी कि इन स्थायी आदेशों का एक वैधानिक आधार था। इस उद्देश्य के लिए धारा 12 पर निर्भरता रखी गई थी। और पुलिस अधिनियम (1861 का 5) के 2 के तहत पुलिस

महानिरीक्षक को ये स्थायी आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। पुलिस अधिनियम की खंड 12 में केवल भौतिक शब्दों को उद्धृत किया गया हैः

> "12. पुलिस महानिरीक्षक, समय-समय पर, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे आदेश और नियम बना सकता है जो वह पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण, जिस स्थान पर बल के सदस्य रहेंगे, और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष सेवाओं के संबंध में समीचीन समझे।"

यह स्पष्ट है कि इस खंड में निर्दिष्ट आदेशों और नियमों का पुलिस में भर्ती अधिकारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण से कोई लेना-देना नहीं है अभिव्यक्ति "संगठन", हमारी राय में, पुलिस बल में उन लोगों की सेवा की 990 शर्तों को इसके दायरे में शामिल नहीं कर सकता है। जिस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, वह भौतिक भाग इसका दूसरा पैराग्राफ है जिसमें लिखा हैः

> "इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन-किसी भी पुलिस बल के अधीनस्थ रैंक के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सभी शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।"

हालाँकि, इस खंड के तहत, यह पुलिस महानिरीक्षक नहीं है, बल्कि राज्य सरकार को पुलिस बल के सदस्यों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार है। यह सुझाव नहीं दिया गया था कि जिन स्थायी आदेशों पर भरोसा किया गया था, वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए थे क्योंकि वे केवल पुलिस महानिरीक्षक के अधिकार में होने का तात्पर्य रखते हैं। एक कमजोर तर्क का यह सुझाव देने का प्रयास किया गया कि राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों को महानिरीक्षक को सौंप

दिया होगा, लेकिन इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि नियम बनाने की शक्ति को व्यक्त वैधानिक प्रावधान के बिना प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

इस तथ्य पर कुछ ध्यान देने की कोशिश की गई कि ये स्थायी आदेश अक्टूबर, 1949 में जारी किए गए थे, जब संविधान नहीं बल्कि धारा 243 भारत सरकार अधिनियम, 1935 लागू था। लेकिन प्रतिवादी को इस परिस्थिति से कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि धारा 243 यह अधिनियमित करता है कि भारत में विभिन्न पुलिस बलों के अधीनस्थ रैंकों की सेवा की शर्तें "ऐसी होंगी जो उन बलों से संबंधित अधिनियमों द्वारा या उनके तहत निर्धारित की जा सकती हैं" और हमें फिर से धारा 2 के प्रावधानों पर वापस फेंक दिया जाता है। पुलिस अधिनियम जिसके द्वारा यह राज्य सरकार है, न कि पुलिस महानिरीक्षक, जिसके पास सेवा की शर्तों को तैयार करने का अधिकार निहित है। इसलिए हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के प्रति बहुत सम्मान के साथ विचार करते हैं कि वे स्थायी आदेश 46 को सेवा की शर्त के रूप में मानने में त्रुटि कर रहे थे, जिसका उल्लंघन प्रत्यर्थी द्वारा अपनी रिट याचिका में आक्षेपित प्रत्यावर्तन के आदेश द्वारा किया गया था।

स्थायी आदेश 46 को अलग रखा जा रहा है, हम धारा 115 अधिनियम के 117 तक की ओर मुड़ते हैं। प्रत्यर्थी नियत दिन पर पुलिस के एक कार्यवाहक उप-निरीक्षक के रूप में अजमेर राज्य की सेवा में था। 1 नवंबर, 1956 और धारा 115 (1) के आधार पर अधिनियम के अनुसार उन्हें राजस्थान राज्य के मामलों के संबंध में सेवा करने के लिए आवंटित किया गया था, और वास्तव में, जैसा कि पहले देखा गया है, 1 नवंबर, 1956 को नियुक्ति का एक औपचारिक आदेश था, जिसके द्वारा उन्हें पुलिस के कार्यवाहक उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। हम-उप धारा 115(5) से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं। जैसा कि, हमारी राय में, कुछ भी इसे चालू नहीं करता है, हालांकि इसे प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया था। इस

अपील के निर्धारण के लिए वास्तव में जो महत्वपूर्ण है वह उप-धाराओं के लिए परंतुक है। उपधारा (7) जिसके द्वारा यह गारंटी थी कि नियत दिन से पहले लागू सेवा की शर्तें केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा प्रत्यर्थी की स्थिति में व्यक्तियों के नुकसान के लिए भिन्न नहीं होंगी। इस परंतुक के तहत उत्पन्न होने वाला प्रश्न यह होगा कि क्या यह किसी कार्यवाहक पद के धारक के लिए लागू सेवा की कोई शर्त है कि उसे अपने मूल पद पर वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे निपटने से पहले, दो अन्य दर्शनों का प्रभाव धारा 117 और धारा 116 (2) में देखा जा सकता है। हम सबसे पहले धारा का उल्लेख करते हैं। क्योंकि यदि अधिकारियों के किसी वर्ग के संबंध में केंद्र सरकार का कोई निर्देश है और इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा निर्देश आवश्यक है, तो इसे लागू करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और ऐसे मामले में यह सवाल कि क्या ऐसा निर्देश सख्ती से सेवा की शर्त है या नहीं, निर्धारण के लिए नहीं आ सकता है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया था और यह उस तर्क का हिस्सा था जिस पर उन्होंने प्रतिवादी को राहत दी थी। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने इस तर्क का समर्थन करने की पुरजोर कोशिश की।

यह निर्देश भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उप सचिव द्वारा राजस्थान सरकार, जयपुर के मुख्य सचिव को 27 मार्च, 1957 को लिखे एक पत्र में निहित होने का दावा किया गया था और इसका शीर्षक था 'राज्य सेवा कर्मियों को प्रदान की जाने वाली सेवा शर्तों का संरक्षण। ' इस पत्र में, उप-धारा 115(7) को परंतुक का उल्लेख करने के बाद उस अधिनियम की जो उप-धाराओं में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों को निर्धारित करता है। केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा उनके नुकसान के लिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा, एक पैराग्राफ पढ़ने के रूप में नीचे दिया गया थाः

"2.(ii) कार्यवाहक वेतन जब कोई अधिकारी वेतन के एक विशेष पैमाने पर लगातार कार्य करता रहा हो या उस पैमाने पर कार्य करता रहा हो, लेकिन उच्च स्तर पर किसी पद पर उसकी कार्यवाहक नियुक्ति या 1 नवंबर, 1956 से ठीक पहले न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़ने के लिए, जिस वेतन पर उसने इस तरह कार्य किया था, उसे संरक्षित किया जाना चाहिए जैसे कि यह एक ठोस क्षमता में लिया गया वेतन और पैमाना हो।"

पत्र में वर्णित विषय-वस्तु को कई भागों में विभाजित किया गया है और उपरोक्त अनुच्छेद 'वेतन' शीर्षक वाले भाग के तहत आता है। प्रत्यर्थी की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया था कि खंड की किसी कार्यवाहक पद पर एक अधिकारी के मूल पद पर प्रत्यावर्तन के प्रश्न के लिए ऐसी कोई प्रासंगिकता थी, या कि अन्यथा भी प्रत्यर्थी वेतन के संबंध में इसमें निहित प्रावधान के लाभ के लिए योग्य था क्योंकि उसने निर्धारित तिथि 1 नवंबर, 1956 से पहले तीन साल की अवधि के लिए उप निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं किया था। हालाँकि, तर्क यह था कि चूंकि इस निर्देश में केवल कार्यवाहक पदों पर आसीन अधिकारियों का उल्लेख किया गया था, इसलिए उस पद पर बने रहने का अधिकार एक सेवा शर्त बन गया और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी बदलाव का आदेश नहीं दिया जा सकता था। हम पहले निकाले गए खंड में निहित निर्देश को पढ़ना संभव नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कुछ अधिकारियों के वेतन की जिस हद तक रक्षा करता है, वह धारा के तहत प्रभावी हो सकता है। अधिनियम की लेकिन उससे परे, धाराओं की उप धारा 115 (7) के परंतुक के अधीन रहते हुए राज्य सरकार की शक्तियों को कम करने का इरादा नहीं है और वास्तव में, वे स्पष्ट रूप से उप-धाराओं द्वारा संरक्षित हैं। धारा

116 (2) जो किसी सक्षम प्राधिकारी को ऐसे व्यक्तियों के संबंध में 'ऐसे पद या पद पर उसके बने रहने को प्रभावित करने वाला कोई आदेश' पारित करने की अनुमति देता है।

केवल यह तर्क बना रहता है कि क्या किसी कार्यवाहक पद पर बने रहने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और क्या यह सेवा की शर्त के रूप में कहा जा सकता है कि ऐसे अधिकारी को उचित कारणों के अलावा वापस नहीं किया जाएगा। हमारी राय में, यह मामला परशोतम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ (1) मामले में इस न्यायालय के फैसले से समाप्त होता है। वहाँ, यहाँ की तरह, एक अधिकारी जिसे सहायक अधीक्षक, रेलवे टेलीग्राफ के रूप में वर्ग आई. टी. सेवा में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, उसकी मूल श्रेणी ।।। नियुक्ति में वापस कर दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रश्न पर विचार किया गया वह यह था कि क्या उस मामले के तथ्यों पर, प्रत्यावर्तन का यह आदेश एक दंड के रूप में पारित किया गया था ताकि अनुच्छेद 311 (2) द्वारा गारंटीकृत संवैधानिक संरक्षण को आकर्षित किया जा सके, लेकिन इस न्यायालय को यह भी विचार करना था कि क्या किसी कार्यवाहक पद पर नियुक्त अधिकारी को उस पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार था (1) [1958] एस. सी. आर. 828 994 इस बारे में दास, सी. जे. ने बहुमत के लिए बोलते हुए कहाः

> "हमारे सामने याचिकाकर्ता को कार्यवाहक आधार पर उच्च पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं था और सामान्य कानून के तहत इस तरह की नियुक्ति की निहित अवधि यह थी कि यह सरकार द्वारा उचित सूचना पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती थी और इसलिए उनकी कमी किसी भी अधिकार को जब्त करने के रूप में काम नहीं करती थी और इसे सजा के रूप में रैंक में कमी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था।"

(बम्बई राज्य में इस न्यायालय के निर्णय वी. पी. ए. अब्राहम को भी देखें)

यदि उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, तो यह प्रतीत होता कि यह उनकी सेवा की शर्तों में से एक थी कि उन्हें प्रशासनिक कारणों से उनकी मूल नियुक्ति में वापस लाया जा सकता था, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि केवल एक मूल पद पर वापस जाना सेवा की शर्तों का भंग है। यही कारण है कि हमने कहा कि उप-धारा(7) धारा 115 के लिए प्रावधान जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा जोर दिया जाता है, वह वास्तव में प्रतिवादी को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। उपरोक्त, सामान्य रूप से, वह तर्क था जिसके आधार पर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने याचिका की अनुमति दी। हम मानते हैं कि ऐसा करने में उनकी गलती थी और तदनुसार अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

अब, उन बिंदुओं में से पहले का उल्लेख करना आवश्यक है जो हमने पहले निर्धारित किए हैं, जिन पर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हम पर कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जिसमें पदोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन किया गया था। यह 12 दिसंबर, 1961 को तय की गई (2) 1961 की सिविल अपील 59 (अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई) की वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया था. अधिकारी राज्य को समग्र रूप से लेकिन क्षेत्रवार मानते हुए और यह याचिका में किए गए इस संबंध में आरोप की गंभीरता थी। इस संबंध में उन्होंने धारा की शर्तों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। 1861 के पुलिस अधिनियम 5 में कहा गया हैः

> "2. राज्य सरकार के अधीन संपूर्ण पुलिस-प्रतिष्ठान, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक पुलिस-बल माना जाएगा, और औपचारिक रूप से नामांकित किया जाएगा; और इसमें इतनी संख्या में अधिकारी

और पुरुष शामिल होंगे, और इसका गठन इस तरह से किया जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश दिया जाए"

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे में राज्य को क्षेत्रों में विभाजित करने और राज्यवार आधार से अलग, क्षेत्रवार वरिष्ठता और पदोन्नति के निर्धारण का बचाव प्रशासनिक विचारों द्वारा किया गया था। विद्वान न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में मामले की इस विशेषता का एक संक्षिप्त संदर्भ दिया है और यह राय व्यक्त की है कि (क्षेत्रवार पदोन्नति की प्रणाली असमानता और कठिनाई का उत्पादक थी। हालाँकि, प्रत्यर्थी के रास्ते में कठिनाई यह है कि इस मामले को देखते हुए उठाई गई याचिका अस्पष्ट, चरित्र की है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमने जिन मुख्य आरोपों और तर्कों से निपटा है, उनके लिए कुछ समर्थन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, न कि पदोन्नति की योजना की संवैधानिक वैधता को बाधित करने के लिए एक स्वतंत्र और विशिष्ट आधार के रूप में। अभिवचनों की इस स्थिति के परिणामस्वरूप इस विवाद को बनाए रखने या दूर करने के लिए आवश्यक तथ्यों और विवरणों को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था, ताकि निश्चित रूप से बिंदु को रिकॉर्ड पर तय नहीं किया जा सके जैसा कि यह है। इस बात को समझते हुए प्रत्यर्थी के वकील ने आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के भंग और पदोन्नति, प्रत्यावर्तन आदि के लिए तैयार की गई क्षेत्रवार वरिष्ठता सूचियों की संवैधानिक वैधता के बारे में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए। सुझाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभिवचनों पर, जैसा कि वे खड़े हैं, इस प्रश्न का संतोषजनक निर्धारण नहीं किया जा सका है। यदि भेदभाव और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के मुद्दे की संतोषजनक जांच आदेशनी है और निर्णय लेना है तो दोनों पक्षों को कई विवरणों पर ध्यान केंद्रित आदेशने के लिए संशोधित अभिवचन दायर आदेशने होंगे, जिसके परिणामस्वरूप यह वस्तुतः एक नई याचिका दायर आदेशने के बराबर

होगा। इसलिए हम मानते हैं कि यदि प्रत्यर्थी को इस तरह की सलाह दी जाती है तो उसे इन अन्य आधारों पर अब विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और यह कि उस उद्देश्य के लिए यह वास्तव में उसके हित में होगा कि उसे आवश्यक आरोप लगाते हुए एक नई याचिका दायर करने और आवश्यक तथ्यों को सामने रखने की अनुमति दी जानी चाहिए जब राज्य को भी ऐसी याचिका पर अपना जवाब देने का अवसर मिलेगा। यह विचार के आलोक में है कि हमने इस बिंदु पर विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने से परहेज किया है।

परिणाम यह है कि अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादी की रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। हमें यह जोड़ना होगा कि यह उस मामले के संबंध में एक नई याचिका दायर करने के उनके अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा, जिसका हमने पहले संकेत दिया है। इस मामले की परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक मयंक चौधरी अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।